P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-5* January- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत–इजरायल राजनीतिक सम्बन्ध

India Isral Political Relation in Culture Perspective

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 27/01/2021, Date of Publication: 28/01/2021

सीता राम चौधरी
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय
किशनगढ़ अजमेर,
राजस्थान भारत

सारांश

एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्प्रभुता के आधार पर जो सम्बन्ध स्थापित किए जाते है उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की श्रेणी में माना जाता है। प्रत्येक देश के अन्य देश के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के विविध आयाम होते है

अफ्रीका, एशिया और युरोप महाद्वीपों को जोडने वाला और अन्धमहासागर, भूमध्यसागर एवं कालासागर से घिरा क्षेत्र पश्चिमी एशिया कहलाता है। पश्चिमी एशिया को एशिया और अफ्रीका का 'प्रवेश द्वार' तथा युरोप का 'पश्चिमी द्वार' भी कहा जाता है। पश्चिमी एशिया में अरमानिया, अजरबेजान, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, जोज्रिया, ईरान, ईराक, इजरायल, जार्डन, टर्की, फिलीस्तीन, लेबनान, सउदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन आदि देश सम्मिलित किए जाते है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलीस्तीन विवाद के समाधान सम्बन्धी अपील को स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा फिलीस्तीन समस्या के अध्ययन हेतु एक आयोग ''युनाइटेड नेशंस स्पेशल कमेटी ऑन फिलीस्तीन'' का गठन 27 अप्रैल 1947 में किया गया। इस आयोग ने 29 नवम्बर 1947 को महासभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में आयोग ने फिलीस्तीन विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। भारत, पाकिस्तान व अरब देशों के प्रतिनिधियों सहित कुल 13 देशों ने फिलीस्तीन विभाजन के विपक्ष में मतदान किया। महासभा द्वारा प्रस्ताव को पारित किए जाने के पश्चात् अरब देशों द्वारा घोषणा की कि महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव को मानने के लिए वे बाध्य नहीं है। उन्हें यह अधिकार है कि वे उसी निर्णय को माने जो उनके विचार में उचित हो।[4] 29 नवम्बर 1947 को फिलीस्तीन विभाजन सम्बन्धी महासभा के प्रस्ताव 181 के पारित होने के पश्चात अरब समुदाय ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनेक सवाल उठाए तथा इस मुद्दे के समाधान हेतु इसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपे जाने कि सिफारिश की। यद्यपि अरबों के विरोध का इस प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने फिलीस्तीन पर मिले मैण्डेट की समाप्ति की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक आवश्यक कार्यकर्ता के रूप में स्वतन्त्र इजरायल राज्य की स्थापना सम्बन्धी घोषणा भी की गई। इस प्रकार यहुदियों के 'राष्ट्रीय घर' की स्थापना सम्बन्धी विचार 14 मई 1948 को वास्तविक बन सका। मई 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता सम्बन्धी इजरायल के आवेदन को स्वीकार कर लिया और इस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा मई 1949 में प्रस्ताव 273(iii) 35 पारित किया गया और इजरायल को संयुक्त राष्ट्र संघ के 59 वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान कि गई। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायल के प्रतिनिधि ने महासभा को आष्वस्त किया कि इजरायल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्तों का पालन करेगा, घरेलु अधिकार क्षेत्र के प्रभावित होने के बावजुद भी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का क्रियान्वयन करेगा[1]

The relations that are established by one nation with another nation on the basis of sovereignty at the international level are considered to be in the category of international relations. Each country has different dimensions to establish relations with other countries.

The region that connects the continents of Africa, Asia and Europe and is surrounded by the Andamasagar, the Mediterranean and the Black Sea is called Western Asia. Western Asia is also known as the 'gateway' of Asia and Africa and the 'western gate' of Europe. West Asia includes countries like Armania, Azerbaijan, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Turkey, Palestine, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen etc.

The United Nations accepted the appeal regarding the resolution of the Palestine dispute. The United Nations Special Committee on Palestine was constituted by the United Nations on 27 April 1947 to study the Palestine problem. This commission presented its report to the General Assembly on 29 November 1947. In this report, the Commission presented a proposal regarding the partition of Palestine, which was accepted by the General Assembly. A total of 13 countries, including representatives from India, Pakistan and Arab countries, voted in opposition to the Palestine partition. After the resolution was passed by the General Assembly, the Arab countries declared that they were not obliged to accept the resolution passed by the General Assembly. They have the right to follow the same decision that they think is appropriate. 4 After the passage of Resolution 181 of the General Assembly of Palestine Partition on 29 November 1947, the Arab community raised many questions regarding this resolution and resolution of the issue. For this to be referred to the International Court of Justice. However, opposition to the Arabs had no effect on this proposal, and on 14 May 1948, Britain announced the end of the mandate on Palestine. Along with this announcement, an announcement was made about the establishment of an independent state of Israel as an essential activist of international politics. Thus, on 14 May 1948, the idea of establishing the 'national house' of the Jews was made real. In May 1948, the Security Council of the United Nations accepted Israel's application for membership of the United Nations and advance action was initiated on it. In this sequence, Resolution 273 (pp) 35 was passed by the United Nations General Assembly in May 1949 and Israel was given membership as the 59th member of the United Nations. On this occasion, Israel's representative in the United Nations assured the General Assembly that Israel would abide by the principles of the United Nations Charter, in spite of the domination of the domestic jurisdiction, it would also implement the resolutions of the United Nations.

मुख्य शब्द : पश्चिमी द्वार' अन्धमहासागर, भूमध्यसागर ,कालासागर ,फिलीस्तीन, मैण्डेट, यहुदी, 'रॉ, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म, सिस्टर डेमोक्रेसी।

Western Gate 'Andhamasagar, Mediterranean Sea, Kalasagar, Palestine, Mandate, Yiddish,' Ra, Palestine Liberation Organization, State Water Utility Reform, Sister Democracy.

प्रस्तावना

राजनीतिक सम्बन्ध

15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से आजाद हुआ। भारत की स्वतन्त्रता से लेकर 27 मई 1964 तक भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ही भारतीय विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। श्री नेहरू ही भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्माणकर्ता रहे। इस दौर में मध्य पूर्व क्षेत्र के प्रति भारतीय विदेश नीति भारत की राजनीतिक स्थिति व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल द्वारा निर्देशित होती रही। जिसके तहत् भारत ने अरब राष्ट्रों व फिलीस्तीन का समर्थन किया।

अक्टुबर 1949 में इजरायल के राजदूत जो अमेरिका में पदास्थापित थे ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू से मुलाकात की। यह मुलाकात इजरायल की मान्यता के संदर्भ में थी। श्री नेहरू ने स्पष्ट किया कि भारत द्वारा इजरायल को मान्यता न दिया जाना भारत के राष्ट्रीय हितों मुख्यतयाः मुस्लिम समुदाय के हितों के अनुरूप है।[1] अनेक दौर की वार्ताओं के पश्चात् 17 सितम्बर 1950 को भारत ने इजरायल को मान्यता दी लेकिन उसके साथ राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना नहीं की गई। जनवरी 1951 में श्रीमान नेहरू ने लंदन में इजरायल के राजदूत इलहयू एप्स्टेन ; म्सपीन म्चेजमपद द्वसे मुलाकात की। श्री नेहरू ने बताया कि राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना से पूर्व कुछ प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा।[2] सितम्बर 1951 में एफ.डब्ल्यू पोलक जो यहुदी एजेन्सी के बम्बई में प्रतिनिधि थे को आधिकारिक रूप से भारत में इजरायल का काउंसल एजेंट बनाया गया।[3]

इजरायल के प्रधानमंत्री डेबिन बेन गुरियन ने भारत–इजरायल सम्बन्धों की प्रगाढ़ता की संभावना को तलाशने हेतु मार्च 1952 में इजरायल के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल वाल्टेयर इयटान को नई दिल्ली यात्रा पर भेजा। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायल के स्थायी सदस्य इबान ने भारतीय समकक्ष विजयलक्ष्मी पंडित से मुलाकात की। भारत–इजरायल के मध्य सम्बन्धों के सामान्यीकरण में एक मुख्य कदम जनवरी 1953 में आया। जब इजरायल ने बम्बई स्थित काउंसल एजेन्सी को काउंसलेट ऑफिस में तब्दील किया गया व ग्रेबियल डोरोन को राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया।[4]

लेकिन उपर्युक्त सभी सार्थक प्रयासों के किये जाने के बाद भी भारत व इजरायल के मध्य सम्बन्धों का सामान्यीकरण नहीं हो पाया। इसके लिए राजनीति विश्लेषकों ने अनेक कारण बताएं जैसे– भारत की मुस्लिम जनता के हितों के साथ भारत खिलवाड़ नहीं करना चाहता था साथ ही भारत की ऊर्जा संसाधनों की प्राप्ति पूर्णतः अरब राष्ट्रों पर निर्भर थी, स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का प्रभाव इत्यादि।

साहित्यावलोकन

किसी भी प्रस्तावित शोध के लिए शोध शीर्षक से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य का अध्ययन उस शोध को सही दिशा देने हेतु अति आवश्यक है। भारत और इजरायल के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालने, उनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में अनेक पुस्तकें, विदेश मंत्रालय के प्रतिवेदन व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के लेख प्रकाशित हुए हैं। भारत की विदेश नीति एवं इजरायल के अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को केन्द्र मानकर अनेक अध्ययन एवं शोध सम्पादित हुए है। इन उपलब्ध शोध साहित्यों में भारत–इजरायल सम्बधों की विस्तृत चर्चा की गई है जिनमें से प्रमुख निम्न हैः–

भारत–इजरायल सम्बन्धों पर पी. आर. कुमार स्वामी द्वारा लिखित ''इण्डियाज इजरायल पॉलिसी''(India's Israel policy) नामक पुस्तक उल्लेखनीय है जिसका प्रकाशन 'कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस' द्वारा वर्ष 2010 में किया गया है। इस पुस्तक में लेखक पी.आर. कुमार स्वामी द्वारा भारत की इजरायल के प्रति विदेश नीति का विश्लेषण किया है। यह पुस्तक भारत के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से ही भारत के यहुदियों के प्रति रूख को स्पष्ट करती है। इस पुस्तक में भारत–इजरायल द्विपक्षीय सम्बन्धों का विस्तृत वर्णन किया गया है साथ ही भारत–इजरायल द्विपक्षीय सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले कारकों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

घसिया ओबेद कायानी द्वारा लिखित पुस्तक ''पोस्ट 9/11 इण्डो–इजरायल रिलेशन्स'' का प्रकाशन 'एल ए पी लेम्बर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग' द्वारा वर्ष 2012 में किया गया है। इस पुस्तक में लेखक कायानी ने अमेरिका पर हुए आंतकवादी हमलों के पश्चात बदले वैश्विक परिदृश्य मे भारत–इजरायल सम्बन्धों को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया के दो प्रमुख देश भारत और इजरायल सामरिक सम्बन्धों के बंधन में एक साथ बंधे हुए है। दोनों देश सुरक्षा से जुडे सामान्य हित के कारण एवं 9/11 की आंतकी घटना से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने हेतु बाध्य हुए है।

इसी क्रम में ''फॉरेन पॉलिसी ऑफ इण्डिया एण्ड वेस्ट एशिया चेंज एण्ड कन्टयुनिटी'' पुस्तक का सम्पादन 'फैजल मोहम्मद और राफ्लुलाह आजमी' द्वारा किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 'न्यू सेंच्युरी पब्लिकेशन', नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014 में किया गया है यह पुस्तक भारत के पश्चिमी एशिया के साथ बहुपक्षीय सम्बन्धों पर विस्तृत प्रकाश डालती है। इस पुस्तक में पश्चिमी एशिया का भारत की ओर आर्थिक झुकाव, ईरान के साथ भारत के आर्थिक सम्बन्ध, भारत की फिलीस्तीन नीति, ऐतिहासिक पहलू, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और फिलीस्तीन

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-5* January- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मुद्दा, भारत–इजरायल सम्बन्धों में फिलीस्तीन कारक, भारत–इजरायल सांस्कृतिक सम्बन्ध, भारतीय यहुदियों की भूमिका, आंतकवाद कि विरूद्ध लड़ाई में भारत–पश्चिमी एशिया सहयोग, अरब जगत पर वैश्वीकरण का प्रभाव इत्यादि विषयों पर विस्तृत प्रकाश डाला है।

भारत–इजरायल सम्बन्धों के अध्ययन से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य के क्रम में ही निकोलस ब्लरेल द्वारा लिखित पुस्तक ''द इवोल्युशन ऑफ इण्डियाज इजरायल पॉलिसी कन्टयूनिटी, चेंज, एण्ड कॉम्परोमाइज सिन्स 1922''उल्लेखनीय है। इस पुस्तक का प्रकाशन 'ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस' द्वारा वर्ष 2015 मे किया गया है। इस पुस्तक में लेखक द्वारा वर्ष 1922 से ही भारत की फिलीस्तीन के प्रति नीति तथा यहूदी लोगों के प्रति भारत के रूख को स्पष्ट किया है। इस पुस्तक में लेखक द्वारा 1948–1956, 1956–1974, 1984–1992 में भारत द्वारा इजरायल के प्रति अपनाए गए भारतीय दृष्टिकोण व भारत इजरायल सम्बन्धों को स्पष्ट किया है साथ ही लेखक द्वारा भारत–इजरायल के मध्य पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के पश्चात् भारत–इजरायल द्विपक्षीय सम्बन्धों का भी विस्तृत उल्लेख किया है।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार की विदेश नीति व आगामी समय में भारतीय विदेश नीति की दिशा क्या होगी साथ ही भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सन्दर्भ में वर्तमान विदेश नीति इत्यादि पहलू को स्पष्ट करने वाली पुस्तक ''मोदी एण्ड द वर्ल्डः द रिंग व्यू इनसाइड आउट'' है। इस पुस्तक का सम्पादन यामिनी चौधरी और अनुसुआदिया चौधरी द्वारा किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2016 में 'बल्यूमसबेरी पब्लिशिंग इण्डिया प्रा. लि.नई दिल्ली' द्वारा किया गया।

विषय विस्तार

भारतीय विदेश नीति के कर्ताधर्ता व मुख्य आर्किटेक्चर तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के निधन के पश्चात् भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री बने। अपने प्रधानमंत्रीत्व कार्यकाल के दौरान भी शास्त्रीजी ने भारतीय विदेश नीति में कोई व्यापक बदलाव नहीं किया और भारत की विदेश नीति मध्य पूर्व के प्रति पहले के समान बनी रही। यद्यपि भारत–पाक युद्ध 1965 के दौरान श्री शास्त्री ने इजरायल से भारी मोटर्रार व गोलाबारूद खरीदने हेतु अपनी सहमति दी।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम कार्यकाल के दौरान भी भारतीय विदेश नीति में इजरायल के प्रति कोई विशेष बदलाव नहीं आया। यद्यपि श्रीमती गांधी ने भारतीय आसूचना एजेन्सी **''रॉ** ; त्ॉद्ृ त्मेमंतबी ंदक ।दंसलेपे ॅपदह द्धके इजरायल की आसूचना एजेन्सी से सहयोग लेने हेतु अपनी सहमति दी तथा पूर्वी पाकिस्तान के स्वतत्रंता संग्राम में इजरायल निर्मित मोटर्रार व गोलाबारूद खरीदे। साथ ही श्रीमती गांधी ने सउदी अरब के उस प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज कर दिया कि भारत को बम्बई स्थित इजरायल के काउसलेट ऑफिस को बन्द कर देना चाहिए।[5] जनवरी 1975 में भारत ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ; च्स्व्दृ च्संमेजपदम स्पइमतंजपवद व्तहंदप्रंजपवद द्धको मान्यता दी व इसके एक मिशन की स्थापना नई दिल्ली में की गई। ऐसा करने वाला भारत गैर–अरब देशों में पहला था। मार्च 1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पी.एल.ओ. के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की। अपने द्वितीय कार्यकाल के दौरान श्रीमती गांधी ने वर्ष 1982 में ग्रीष्मकाल में भारत में इजरायल के मुम्बई स्थित काउंसलर को निष्कासित कर दिया क्योंकि उसके द्वारा मीडिया में इजरायल के प्रति भारत के रवैये की आलोचना की जा रही थी। श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्रीत्व काल के इस दौर में भारत–इजरायल सम्बन्ध निम्नतम स्थान पर रहे।[6]

स्वतन्त्रता के बाद मार्च 1977 में पहली बार भारत में गठबन्धन सरकार का गठन हुआ। इस गठबन्धन सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया। इस दौर में अगस्त 1977 में इजरायल के विदेश मंत्री मोसी डायन एक गुप्त यात्रा पर नई दिल्ली आए। श्रीमान देसाई ने डायन से कहा कि भारत–इजरायल के मध्य पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक इजरायल अरब भूमि पर किए गए अधिग्रहण को छोड़ नहीं देता। इस वक्तव्य पर डायन ने अपनी असहमति व्यक्त की।[7] कैम्प डेविड समझौते के पश्चात् इजरायल के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन आया तथा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इजरायल के रक्षा मंत्री एजर वाइझमन से लंदन में मुलाकात की। इजरायल के रक्षा मंत्री ने भारत को तकनीकी क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव दिया। इसी सम्भावना को देखते हुए श्री देसाई ने अपने मुख्य निजी सचिव वी.शंकर को वर्ष 1979 में इजरायल की यात्रा पर भेजा लेकिन दोनों देषों के सम्बन्ध एक नए पायदान पर पहुंच पाते उससे पूर्व ही भारतीय सरकार का विघटन हो गया।

प्रधानमंत्री चरण सिंह के लघु कार्यकाल के दौरान भी भारत–इजरायल सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं आया। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री द्वारा इजरायली अधिकारियों व राजनेताओं से खुली मुलाकात की जाने लगी तथा मुम्बई स्थित इजरायल के काउन्सलर ऑफिस को पुन खोला गया। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और चन्द्रशेखर के कार्यकाल में भी भारत–इजरायल सम्बन्धों में कोई प्रगति नहीं हुई।

वर्ष 1991 में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में अनेक परिवर्तन आए जिनमें मुख्य था–शीतयुद्ध का अंत जिसने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को परिवर्तित कर दिया। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आया और विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में तब्दील हो गई जिसमें सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आया और विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में तब्दील हो गई जिसमें सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च शक्ति बन गया

साथ ही इस एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संकेत स्पष्ट दिखाई देने लेगे।

उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के पश्चात भारत में भी अनेक परिवर्तन आए तथा भारत में श्री पी. वी. नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री बने। श्री राव ने सत्ता में आते ही मध्य पूर्व के प्रति मुख्यतया भारत की इजरायल के प्रति विदेश नीति में बदलाव के संकेत दिए। सितम्बर 1991 में भारत के विदेश मंत्री महादेव सिंह सोंलकी ने इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की संभावना व्यक्त की। लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं बताई। नवम्बर 1991 में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में इस संदर्भ में प्रभावपूर्ण बहस हुई। इस अवसर पर अनेक भारतीय सासंदों यथा–प्रमोद महाजन, रामजेठमलानी, सुब्रह्मण्यम स्वामी, यसवंत सिन्हा इत्यादि ने इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना हेतु अपना विचार रखा।[8] प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिम्हा राव के कार्यकाल के शुरूआती दौर में ही इजरायल के प्रति भारतीय विदेश नीति में व्यापक बदलाव तब आया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 3379 के निरसन के पक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव यहुदीवाद को प्रजातिवाद के समान मानने के सम्बन्ध में था। यद्यपि 1975 में जब यह प्रस्ताव लाया गया तब भारत इसका सह–संस्थापक था। भारतीय विदेश नीति में आए इस बदलाव की मीडिया, विपक्षी दलों व काग्रेंस सदस्यों द्वारा आलोचना की गई। किन्तु फिर भी सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही।[9]

दिसम्बर 1991 में भारत में बम्बई स्थित इजरायल के काउन्सलर ऑफिस में पदास्थापित काउन्सलर गिओरा बेचर को प्रथम बार विदेश मंत्रालय की मीटिंग में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की। पूर्वोत्तर सभी बदलावों के साथ–साथ भारत के विदेश मंत्रालय ने 17 जनवरी 1992 को यह घोषणा की कि सरकार द्वारा इजरायल के प्रति भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है तथा भारत के विदेश मंत्रालय ने इस तथ्य को दोहराया कि भारत फिलिस्तीन का पूर्ण समर्थन करता है।[10] इजरायल के प्रति भारत की विदेश नीति में बदलाव लाने हेतु आधार तैयार करने हेतु भारतीय प्रधानमंत्री श्री राव ने फिलीस्तीन मुक्ति संगठन के नेता यासिर अराफात को आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया।[11] अपनी भारत यात्रा के दौरान यासिर अराफात ने भारत के इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना सम्बन्धी इरादे का विरोध नहीं किया और कहा कि ''पूर्ण राजनयिकों सम्बन्धों की स्थापना, राजनयिकों की अदला–बदली व मान्यता देना सम्प्रभुता का कार्य है जिसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता।''[12]

यासिर अराफात से मिले अनुसमर्थन के पश्चात् भारत ने इजरायल से सम्बन्धों के सामान्यीकरण हेतु वार्तालाप शुरू की। इसी संदर्भ में 22 जनवरी 1992 की मध्यरात्रि को भारत के विदेश सचिव जे.एन.दीक्षित से मुलाकात हेतु इजरायल के मुम्बई स्थित काउंसलेंट ऑफिस के काउसंलर गिओरा बेचर को नई दिल्ली बुलाया गया।

विदेश सचिव जे.एन.दीक्षित के अनुसार राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के विषय पर विचार–विमर्श हेतु 23जनवरी 1992 को केबिनेट मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई जिसमें इस विषय पर विचार–विमर्श किया गया। जिसमें केवल मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने भारत की विदेश नीति में आने वाले इस बदलाव का विरोध किया। उनका मत था कि इजरायल के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण से मुस्लिम बहुमत प्रभावित होगा। साथ ही यह निर्णय भारत की विदेश नीति के नेहरूवादी दृष्टिकोण को सुचारू रखने में भी बाधक होगा।[13]

29 जनवरी 1992 को भारत के विदेश सचिव जे.एन.दीक्षित ने भारत व इजरायल के सम्बन्धों का दर्जा बढ़ाने हेतु इजरायल के काउंसलर गिओर बेचर को बुलाया। इसके पश्चात् भारत व इजरायल के मध्य पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की घोषणा की गई। 12 फरवरी 1992 को इजरायल के विदेश मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि मुम्बई में पदस्थापित काउंसलर ही अस्थायी रूप से नई दिल्ली में इजरायल के राजदूत होगे। मार्च 1992 में नई दिल्ली के मेरिडेन होटल में इजरायली दूतावास अस्थायी रूप से खोला गया। मई 1996 में इजरायल व जून 1996 में भारत में सम्पन्न हुए संसदीय चुनावों के पश्चात् दोनों देशों में पूर्व से भिन्न राजनीतिक दलों ने सत्ता प्राप्त की जो भारत, फिलिस्तीन मुद्दे पर असहमति रखता था। इसी प्रकार भारत में यूनाइटेड फ्रंट गठबन्धन ने सत्ता प्राप्त की। इस गठबन्धन का नेतृत्व जनता दल द्वारा किया जा रहा था जिसने सन् 1992 में इजरायल के साथ राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना पर आपति व्यक्त की थी। इस दौर में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान एच.डी.देवेगोडा थे। इस सरकार के दौरान पहली बार इजरायल के राष्ट्रपति एजर वाइझमन ने दिसम्बर 1996–जनवरी 1997 में भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वाइझमन व देवेगोडा ने अनेक समझौते सम्पन्न किए।[14] देवेगोडा के उत्तराधिकारी बने आई.के.गुजराल के कार्यकाल के दौरान भारत व इजरायल के सम्बन्ध सामान्य बने रहे।

भारत व इजरायल के मध्य सम्बन्धों में विशेष प्रगति राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा था के शासन काल में हुयी इस शासनकाल के दौरान भारत ने प्रो–एक्टिव इजरायल पॉलिसी को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप ही भारत व इजरायल के मध्य अधिक उच्च स्तरीय यात्राएँ हुयी जैसे–जून 2000 में भारत के उपप्रधानमंत्री व गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इजरायल की यात्रा की तथा जुलाई 2000 में भारत के विदेश मामलों के मंत्री जसवंत सिंह ने इजरायल की यात्रा की। राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन के शासन काल के दौरान भारत–इजरायल सम्बन्ध एक नए पायदान पर तब पहुंचे जब भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निमंत्रण पर पहली बार इजरायल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने 8 से 10 सितम्बर 2003 को भारत यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री शेरोन की इस यात्रा के दौरान इजरायल के उपप्रधानमंत्री और न्यायमंत्री योसफ

लेपीड, संस्कृति, शिक्षा व खेल मंत्री लिमोर लिवेन्ट, कृषि मंत्री इजरायल काट्ज तथा सांस्कृतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधि मण्डल ने भी भारत की यात्रा की। अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शेरोन ने राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वार्तालाप किया। इसके साथ ही इन्होंने गृहमंत्री, रक्षामंत्री, वित्तमंत्री व विदेशमंत्री के साथ भी भारत इजरायल सम्बन्धों पर विस्तृत विचार विमर्ष किया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के मध्य अनेक समझौते जैसे–पर्यावरण संरक्षण हेतु समझौता, हेल्थ व मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग समझौता सम्पन्न हुए। प्रधानमंत्री शेरोन ने भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी को इजरायल आने का न्यौता दिया जिसे प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया।[15] मई 2004 में सम्पन्न हुए भारतीय संसद के चुनावों से पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर अपनी सहमति दी। यह कार्यक्रम भारत की पश्चिमी एशिया नीति के पुनः संतुलन तथा फिलिस्तीन के समर्थन की पुनः स्वीकारोक्ति के संदर्भ में भी था। सता प्राप्ति के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की दिशा निर्धारित करने हेतु सरकार (संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस, साम्यवादी दल व अन्य दल सम्मिलित थे) ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम को ध्यान में रखा। इस शासन काल में भारत व इजरायल के मध्य बहुत ही कम उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएँ हुई तथा बहुत ही कम आधिकारिक वक्तव्य जारी हुए।

इस सरकार में विदेश मंत्री श्रीमान नटवर सिंह को बनाया गया जो भारतीय जनता पार्टी की इजरायल से सम्बन्धों को बढ़ावा देने की नीति की आलाचेना करते रहे हैं।[16] नटवर सिंह को विदेश मंत्री बनाए जाने के पश्चात् इन्होंने कहा कि भारत–इजरायल के साथ सम्बन्धों की महता को समझता है और फिलिस्तीन के साथ सम्बन्धों में कोई बदलाव नहीं लाएगा।[17] वर्ष 2005 में नटवर सिंह ने कहा कि भारत के अरब जगत के साथ प्रगाढ़ आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे है और फिलिस्तीन के लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए भारत के समर्थन को साबित किया जाएगा। इस दौर में भारत–इजरायल सम्बन्धों में दूरियां बढ़ने लगी। भारत के रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने घरेलू राजनीति के प्रभाव के कारण जुलाई 2006 में अपनी इजरायल यात्रा को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने वर्ष 2007 में होने वाली इजरायल यात्रा को अन्तिम समय में निरस्त कर दिया गया। इजरायल के विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारी का कहना था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के कार्यकाल के दौरान उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्राओं की कमी रही।[18]

यद्यपि संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के द्वितीय कार्यकाल में भारत–इजरायल सम्बन्धों में सुधार हुआ। भारत–इजरायल के मध्य पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत के विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने इजरायल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत व इजरायल के मध्य प्रत्यर्पण सन्धि 10जनवरी 2012 को हुई तथा विदेश मंत्री श्री कृष्णा ने इजरायल के काउंसलेट जनरल का ऑफिस भारत के शहर बेंगलौर में भी खोलने की घोषणा की।[19]

मई 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के भारतीय प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अनेक राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा यह कयास लगाया जाने लगा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताओं व लक्ष्यों को पुनः निर्धारित किया जाएगा। इस तथ्य का प्रमाण श्रीमान मोदी द्वारा अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित कर दिया जो भारतीय विदेश नीति में एक नया उदाहरण देखने को मिला। श्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् इजरायल से द्विपक्षीय सम्बन्धों को मधुर बनाने हेतु प्रयास किए जाने लगे इन्हीं प्रयासों में से मुख्य हैं–

संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने गए श्री मोदी ने सितम्बर 2014 में न्यूयार्क में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से द्विपक्षीय सम्बन्धों को मधुर बनाने के सम्बन्ध में मुलाकात की।[20] इन्हीं प्रयासों को गति देने हेतु इजरायल के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2015 तक इजरायल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इजरायली संसद नैसेट को सम्बोधित किया। 15 अक्टूबर 2015 को हिब्रु विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, रक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु अनेक मेमोरेण्ड ऑफ अण्डरस्टेडिंग (एम.ओ.यू.)सम्पन्न हुए।

इसी प्रकार भारत सरकार में विदेश मामलों की मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने विदेश मामलों के मंत्रालय के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ 17–18 जनवरी 2016 को इजरायल की आधिकारिक यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान श्रीमती स्वराज ने इजरायल के नेताओं से भारत–इजरायल द्विपक्षीय सम्बन्धों पर विस्तार से चर्चा की। अपने मीडिया वक्तव्य में श्रीमती स्वराज ने कहा कि भारत व इजरायल दोनों ही देश खुली अर्थव्यवस्था व लोकतान्त्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते है। भारत व इजरायल कृषि क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व शिक्षा के क्षेत्र में निकट सम्बन्ध रखते हैं। दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने हेतु और अधिक सार्थक प्रयास करना चाहिए। इस यात्रा के दौरान श्रीमती स्वराज ने इजरायल में निवासित भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की।[21]

दोनों देशों के सम्बन्धों को ओर अधिक प्रगाढ़ बनाने हेतु श्रीमान मोदी द्वारा सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टस में कहा जा रहा है कि भारत–इजरायल के मध्य पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों के 25 वर्ष पूरे हो गए। इसी सुअवसर पर श्रीमान मोदी इजरायल की यात्रा करने वाले थे।[22] इन्हीं आषंकाओ के अनुरूप भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जुलाई 2017 में इजरायल की यात्रा की। भारत–इजरायल सम्बन्धों में एक नए युग की षुरूआत भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 4–6 जुलाई 2017 को की गई इजरायल यात्रा से हुई

है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने यह यात्रा भारत–इजरायल के मध्य राजनयिक सम्बन्धों के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में की गई है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इजरायल की यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है। इस यात्रा के दौरान श्रीमान मोदी का इजरायल में गर्मजोषी से तथा भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान श्रीमान मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से भारत–इजरायल सम्बन्धों पर विस्तृत विचार विमर्ष किया। इस यात्रा के दौरान भारत–इजरायल के मध्य सात करार सम्पन्न हुए जो निम्न है[23]:–

1. भारत–इजरायल के मध्य इण्डस्ट्रियल आर एण्ड डी टेक्नोलोजी इनोवेषन फण्ड की स्थापना के लिए भारत के विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी मंत्रालय और इजरायल के नेषनल अथॉरिटी फॉर टेक्नोलोजी इनोवेषन के मध्य मेमोरेंण्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिग(एम. ओ.यू.)। यह फण्ड 40मिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा जिसमें दोनों देषों का समान अषंदान होगा ।
2. इजरायल जल संरक्षण और जल प्रबंधन में भारत की मदद करेगा।
3. भारत के उत्तरप्रदेष राज्य में पानी की जरूरतों को पूरा करने हेतु ''स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म '' एम. ओ.यू.।
4. कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता।
5. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सगंठन और इजरायल स्पेस एजेन्सी के मध्य परमाणु घडी के सम्बन्ध में समझौता।
6. अन्तरिक्ष क्षेत्र में नैनो सेटेलाईट के सन्दर्भ समझौता।
7. जी ई ओ–एल ई ओ ऑप्टिकल लिंक में कॉपरेषन के लिए एम.ओ.यू.।

प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और इजरायल को दो ''सिस्टर डेमोक्रेसी'' बताया साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ''ये बहुत महान दिन है। मेरे दोस्त मोदी इतिहास बना रहे हैं हम सब मिलकर आतंकवाद से लडेंगें।''[24] भारत–इजरायल सम्बन्धों के सम्बन्ध में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते ''वैवाहिक सम्बन्धों'' जैसे है। यह रिश्ता स्वर्ग में बनी शादी है लेकिन हम इसे यहाँ धरती पर लागू कर रहे है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा भारत इजरायल सम्बन्धों के सन्दर्भ में व्यक्तव्य और भारत की प्रषंसा की उसी प्रकार भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी ने भी अपने व्यक्तव्य में कहा कि ''भारत दिक्कतों से लडकर कामयाबी हासिल करने के लिए इजरायल के लोगों की तारीफ करता है हो सकता है कि हमारे रास्ते अलग–अलग हो लेकिन लोकतान्त्रिक मूल्यों और आर्थिक विकास के लिए हमारा मकसद एक जैसा हैं।[25]

अपनी इजरायल यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति रिवेन रिवलिन से भी भेंट कर आपसी सम्बन्धों की बेहतरी पर चर्चा की। इजरायल को सच्चा दोस्त बताते हुए श्रीमान मोदी ने कहा कि ''हमारा रिष्ता आई से आई का है।'' आई के लिए आई का मतलब इण्डिया और आई का मतलब इजरायल। इस प्रकार भारत इजरायल के लिए तथा इजरायल भारत के लिए है।'' [26]

निष्कर्ष

भारत द्वारा द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों के समान ही इजरायल भी इस सन्दर्भ में प्रयास करता रहा है। इन्हीं प्रयासों के क्रम में इजरायल के राष्ट्रपति रियुवेन रिवलिन 14 से 21 नवम्बर 2016 तक 6 दिवसीय भारत यात्रा पर आए जो कि करीब 20 साल में इजरायल के किसी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। यद्यपि रियुवेन रिवलिन से पूर्व राष्ट्रपति एजर वाइझमन ने 1996–97 में भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान रियुवेन रिवलिन ने भारत के राष्ट्रपति श्री प्रवण मुखर्जी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की। भारत दौरे पर निकलने से पहले इजरायल के राष्ट्रपति रिवलिन ने कहा कि वो एक महत्वपूर्ण दौरे पर भारत जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और इजरायल के रिश्ते बहुत मजबुत है और इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में और भी मजबूती आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह दौरा दोनों देशों के मजबूत रिश्ते और दोस्ती का प्रतीक है और उन्हें आशा है कि इस दौरे के बाद ये दोस्ती और भी घनिष्ठ हो जाएगी। जून 2019 में भारत ने पहली बार इजरायल के समर्थन में यूएन में मतदान किया। हालांकि इजरायल हमेशा ही भारत का रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करता रहा । मार्च 2020 मे भारत ने इजरायल के साथ 880 कारोड का रक्षा सौदा किया। लेकिन दोनो देषों को द्विपक्षीय संभावनाओं तथा कारोबार और निवेष का दोहन करने के लिये और कदम उठाने की जरूरत है। [27]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सिमोन एनिमोर (सम्पादक), ''रिलेशन बिटविन इजरालय एण्ड एशियन एण्ड अफ्रीकन स्टेटसः ए गाइड टू सलेक्टेडेड डॉक्यूमेटेशन'', द हिब्रु युनवर्सिटी आफॅ जेरूसलम, माओर वाल्लच प्रेस लिमिटेड, जेरूसलम, 1991 पृ. 172*
2. *इजजैक गेर्बर्ग, ''द चेंजिगिग नेचर ऑफ इजरायली इण्डियन रिलेशनसः1948–2005'', युनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रिटोरिया, 2008पृ. 79*
3. *पी. आर. कुमारस्वामी, ''इण्डियाज इजरायल पॉलिसी'', कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 2010 पृ.126*
4. *पी. आर. कुमारस्वामी, ''इण्डियाज इजरायल पॉलिसी'', कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 2010, पृ.129*
5. *द पायनियर, 21 जून 2004*
6. *सुब्रण्यम स्वामी ''द सेक्रेट फ्रेंडशिप बिटविन इण्डिया एण्ड इजरायल'', संडे,वाल्युम 10, नम्बर 21, 28 नवम्बर–4 दिसम्बर कलकत्ता, इण्डिया, पृ. 22*
7. *सुब्रण्यम स्वामी ''द सेक्रेट फ्रेंडशिप बिटविन इण्डिया एण्ड इजरायल'', संडे, वाल्युम 10, न. 21, 28 नवम्बर–4 दिसम्बर कलकत्ता, इण्डिया, पृ. 21*

8. *इजजैक गेर्बर्ग, ''द चेंजिंग नेचर ऑफ इजरायली–इण्डियन रिलेशनस:1948–2005'', युनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रिटोरिया, 2008 पृ. 141*
9. *निकोलस ब्लरेल, ''द इवोल्युशन ऑफ इण्डियाज इजरायल पॉलिसी : कन्टीन्यूटी, चेंज एण्ड काम्परोमाइज सिन्स 1922'', आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 2015, पृ. 243*
10. *टाईम्स ऑफ इण्डिया, 18 जनवरी 1992*
11. *जे एन दीक्षित, ''माई साउथ ब्लॉक ईयरस : मेमोरिज ऑफ ए फोरेन सेक्रेटरी'', यूबीएस पब्लिशर्स, नई दिल्ली 1996, पृ. 309*
12. *द इण्डियन एक्सप्रेस, 20 जनवरी 1992*
13. *जे एन दीक्षित, ''माई साउथ ब्लॉक ईयरस : मेमोरिज ऑफ ए फोरेन सेक्रेटरी'', यूबीएस पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1996 पृ. 311*
14. *द पायनियर , 9 जनवरी 1997*
15. *दिल्ली स्टेटमेंट ऑन फ्रेंडशिप एण्ड कॉपरेशन बिटविन इण्डिया एण्ड इजरायल, 10 सितम्बर 2003*
16. *द हिन्दु, 22 अक्टूबर 2000*
17. *द टाईम्स ऑफ इण्डिया, 12 जुलाई 2004*
18. *द इण्डियन एक्सप्रेस, 14 जून 2011*
19. *निकोलस ब्लरेल, ''द इवोल्युशन ऑफ इण्डियाज इजरायल पॉलिसी, कन्टीन्यूटी चेंज एण्ड कॉम्परोमाइज सिन्स 1922'', आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 2015 पृ. 269*
20. *यामिनी चौधरी, अनुसूदिया चौधरी, ''मोदी एण्ड द वर्ल्ड द रिंग व्यू इनसाइड आउट'' ब्लूमसबरी पब्लिशिंग इण्डिया प्रा. लिमिटेड, 2016, पृ. 249*
21. *pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=13484*
22. *अंकित पाण्डा, ''नरेन्द्र मोदी टू बिकम फर्स्ट इण्डियन पीएम टू विजिट इजरालय'' द डिप्लोमेट, 2 जून 2015*
23. *List of MoUs /Agreements signed during the visit of prime minister to Israel(july5,2017)*
24. *http://www.mea.gov.in/bilateral - documents.htm?dtl/28592/List+of+MoUsAgreements+signed+ during+ the+ visit+ of+ prime+ minister+ to+ Israel+july+5+2017*
25. *राजस्थान पत्रिका, जयपुर संस्करण, 6जुलाई 2017,पृ. स. 5*
26. *दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण ,नईदिल्ली, 6जुलाई 2017,पृ.स.1*
27. *दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण ,नईदिल्ली, 6जुलाई 2017,पृ.स.1*
28. *जागरण, नवम्बर 2020*